



C. P. S. 101-2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
पुनर्विलोकन प्रकष क्रमांक 1.05

शेक 914-II/2005

श्री के. के. द्विवेदी - एडवोकेट  
द्वारा आज दि. 22/6/05 को प्रस्तुत।  
अवकाश सचिव  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
27 JUN 2005

हरी सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत  
निवासी ग्राम बडोदा बुंद तहसील  
राधोगढ जिला गुना म.प्र.।  
..आवेदक

विस्त  
कस्तूरी बाई पत्नी मोती जी मील  
निवासी ग्राम बहा दुरपुर तहसील  
राधोगढ जिला गुना म.प्र.।  
... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकष क्रं. 379 1/05में  
पारित आदेश दिनांक 4.5.05 के विस्त म.प्र. मू.  
राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन  
आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश में कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं इस कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उठाई गयी आपत्तियों पर न तो विचार किया और न ही निर्णय इस कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।  
इस संदर्भ में सिमनलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है.

27-6-05  
K. K. Dwivedi  
Advocate

2  
3-7/05  
अपील  
अपील

14

454

allan

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 914-दो/2005

[ट्रीप्ट] कुरुरीवाइ

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-11-2016	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-5-05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4-5-05 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</li> <li>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या</li> <li>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण</li> </ol> <p>आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।</p> <p>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>